सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-9 7 मई से 21 मई 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

देशभर में एसयूसीआई(सी) का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया

24 अप्रैल को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी का 63वां स्थापना दिवस देश भर में यथोचित ढंग से मनाया गया। इस दिन पार्टी कार्यालयों पर लाल झंडा फहराया गया, सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उनके बैज धारण किये गये। जगह-जगह सभाएं आयोजित की गई। सभाओं की शुरूआत इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार व पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत से हुई और समापन अंतर्राष्ट्रीय गान के साथ हुआ।

कोलकाता में 24 अप्रैल को कॉ. शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए पार्टी के महासचिव कॉ. प्रभाष घोष

दिल्ली में 24 अप्रैल को सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

दिल्ली : एस.यू.सी.आई.(सी) की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व लोगों ने 24 अप्रैल को पार्टी का 63 वां स्थापना दिवस मनाने के लिए मुकुंदपुर, दिल्ली में आयोजित जनसभा में भाग लिया। सभा स्थल को लाल झंडों से सजाया गया था। पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे। दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल व राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉमरेड मैनेजर चौरसिया वक्ता थे। सभा की अध्यक्षता दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉमरेड प्राण शर्मा द्वारा की गयी।

दिल्ली सरकार द्वारा पानी के शोधन और वितरण के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ एक प्रस्ताव सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। पानी के शोधन और वितरण को निजी हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनआंदोलन को और भी बल मिला जब इस कदम के खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के फार्म पर सभा के मुख्यवक्ता कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर करके अभियान की शुरूआत की।

रोहतक (हरियाणा) : 24 अप्रैल को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के 63वें स्थापना दिवस पर छोटूराम पार्क सभागार में राज्य स्तरीय जनसभा आयोजित की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं, हमदर्दों, व समर्थकों से हाल खचाखच भरा था। जनसभा में मुख्य वक्ता पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती थे। पार्टी की हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव व केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य कॉ. अनूपसिंह ने की।

कॉमरेड सत्यवान ने हुड्डा सरकार द्वारा कृषि भूमि के अधिग्रहण करने शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को महंगा करने व निजी हाथों में देने, देहात व शहर में गृहकर (चूल्हा टैक्स) दुबारा थोपने, बिजली दर व रजिस्ट्री के रेट बढ़ाने और महिलाओं समेत आम आदमी पर अपराधों व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कड़ी निन्दा की।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

झारखंड में हुई पुलिस फायरिंग की एसयूसीआई(सी) द्वारा कड़ी निन्दा

धनबाद, झारखंड में हुई पुलिस फायरिंग की निन्दा करते हुए एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 28 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी निर्माण के लिए प्रोमोटरों व ठेकेदारों को खाली जमीन सौंपने के घृणित उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर जिस तरह से बीजेपी-नीत झारखंड सरकार पिछले 50-60 सालों से बासिन्दे हजारों झुग्गी-झौपड़ीवासियों को बेदखल कर रही है और उन्हें रास्ते का भिखारी बना रही है वह बेहद क्रूर और अमानवीय है, सत्ता में चाहे कोई भी रहा हो, भारत में जनआन्दोलन को क्रूरता से कुचलने के इतिहास में जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है।

हमें यह जानकर दुख पहुँचा कि इस मुहिम के दौरान झारखंड सरकार ने रांची में कुछ दिन पहले एक बच्चे समेत दो निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और कल धनबाद में पुलिस ने आन्दोलनकारियों पर एके-47 राइफलों से लगभग एक हजार राउण्ड गोलीबारी की जिसमें 6 लोग मारे गये और 16 लोग घायल हुए। इस क्रूर हत्याकान्ड की हम कड़ी निन्दा करते हैं और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि (1) इस नाजायज बदेखली को तुरंत रोका जाये, (2) मृतकों के परिवार वालों व घायलों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये, (3) घायलों के उचित इलाज की आर्थिक जिम्मेदारी सहित तमाम जिम्मेदारियाँ ली जायें, (4) दोषी पुलिस अफसरों को कड़ी और उदाहरणमूलक सजा दी जाये।

जापान में नाभिकीय तबाही
क्या अब भी कोई नाभिकीय विद्युत उत्पादन की वकालत कर सकता है

अभूतपूर्व तीव्रता के भूकम्प और इसके चलते पैदा हुई सुनामी ने जापान के पूर्वी तट के विशाल क्षेत्रों में जबरदस्त तबाही मचाई है। इसने जापान को नाभिकीय महाविपत्ति के कगार पर ला खड़ा किया है। क्षत-विक्षत फुकुशिमा दाइची-न्युक्लियर पावर प्लांट से उत्पन्न खतरे ने पुन: एक बार नाभिकीय विद्युत उत्पादन की सुरक्षा और बचाव के सवाल को केन्द्र में ला दिया है। जब भूकम्प आया तब रिएक्टर की नियंत्रक छड़ें स्वत:स्फूर्त सक्रिय हो गई और रिएक्टरों को बन्द कर दिया। फिर भी ठंडा करने की प्रणाली फेल हो गई क्योंकि सुनामी ने एमरजेंसी जेनरेटरों सहित पावर सप्लाई क्षतिग्रस्त कर दी। नतीजतन, ईंधन छड़ें और नियंत्रक छड़ें गर्म होनी शुरू हो गई और रिएक्टर के मध्य भाग क्षतिग्रस्त कर दिये। पहले ही कई धमाके हो चुके हैं जिन्होंने रिएक्टर बेकार कर दिये हैं। सुनामी के बाद एक महीना गुजर जाने के पश्चात् भी रिएक्टर काबू में नहीं लाये जा सके हैं। रेडियोधर्मी रिसाव जारी है और रिएक्टर के मध्य भागों के पिघलने का विनाशकारी खतरा मंडरा रहा है। रेडियोधर्मी संदूषण हवा, मिट्टी, सतही जल, भूमिगत जल और समुंद्री जल में पाया गया है और संदूषण खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर गया है। खतरे के आयाम को अब 7 प्वाइंट इंटरनेशनल न्युक्लियर इवेंट स्केल (आईएनईएस) के सर्वोच्च स्तर 7 का दर्जा दिया गया है।

लम्बे अर्से से नाभिकीय उर्जा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। अनेक वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और चिंतित नागरिकों ने अनेक कारणों से उर्जा उत्पादन में नाभिकीय विकल्प को अपनाने के औचित्य पर सवाल उठाए थे, जिनमें एक प्रमुख समस्या रेडियोधर्मी कचरे के निपटारे, नाभिकीय विखंडन के अंतर्निहित खतरनाक चरित्र और विशेषकर किसी दुर्घटना के विनाशकारी परिणाम की है। लेकिन सरकारों और सत्ताधारियों ने आम तौर पर इन एतराजों को कोई तवज्जो नहीं दी और नाभिकीय उर्जा उत्पादन पर अड़े रहे, यह मानते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने का यही एकमात्र तरीका है। जापान के हादसे ने एक बार पुन:

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जापान में तबाही...

(पृष्ठ 1 का शेष)

नाभिकीय रिएक्टरों की असुरक्षित स्थिति को साफ तौर से उजागर कर दिया है। जनता के मूड को भांपते हुए विभिन्न सरकारें अपने नाभिकीय संयंत्रों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और अपनी भावी नाभिकीय योजनाओं की पुनः जांच-पड़ताल करने के लिए सहमत हुई हैं। नाभिकीय उर्जा पर पूरी बहस ने एक नया आयाम ले लिया है।

न्युक्लियर पावर प्लांटों में अतीत में हुई दुर्घटनाएं

स्मरण रहे कि फुकुशिमा की तबाही कोई पहली नाभिकीय दुर्घटना नहीं है; पहले भी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 1957 में खुश्चेव-नीत सोवियत यूनियन में किश्तिम की तबाही में रेडियोधर्मी कचरे के लिए भण्डारण टैंक में ठंडा करने की प्रणाली फेल हो जाने की वजह से विस्फोट हो गया और भारी मात्रा में रेडियोधर्मिता का रिसाव हो गया था। 12 घंटों से भी कम समय में रेडियोधर्मिता 300-350 कि.मी. की दूरी तय कर गई थी और इसके नतीजतन 800 वर्ग कि.मी. से ज्यादा इलाका लम्बे अर्से तक प्रदूषित रहा था। लेकिन संशोधनवादी सोवियत नेतृत्व द्वारा इस खबर को अनेक सालों तक दबा कर रखा गया। अमेरिकी खुफिया विभाग को भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने नई-नई उड़ान भरना सीख रही न्युक्लियर इंडस्ट्री को जनता की निगरानी से बचाए रखने के लिए इसका प्रचार नहीं किया। 1979 में अमेरिका में थ्रीमाइल दुर्घटना में ठंडा करने की प्रणाली के फेल हो जाने की वजह से मध्य भाग का आंशिक हिस्सा पिघल गया था। तकनीकी विफलता, डिजाइन की त्रुटि और अपर्याप्त ट्रेनिंग की वजह से हुई इन्सानी भूल को दुर्घटना के कारणों के रूप में बताया गया था। अति रेडियोधर्मी कूलेंट का रिएक्टर की बिल्डिंग के बाहर रिसाव हो गया था और अधिकारियों ने रिसे हुए रेडियोधर्मी 40000 गैलन वेस्ट वाटर को सीधे सस्क्युहाना नदी में छोड़ दिया। 1986 में चेर्नोबिल तबाही एक विनाशकारी दुर्घटना थी और अति रेडियोधर्मी धुँए का गुब्बार वायुमण्डल में फैल गया था। संयंत्र और आस-पास के इलाके रेडियोधर्मिता से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। रेडियोधर्मी गुब्बार पश्चिमी सोवियत यूनियन और यूरोप के विशाल क्षेत्र पर फैल गया था और बेलारूस, रूस और युक्रेन के क्षेत्रों को भयंकर रूप से प्रदूषित कर दिया था। इस गुब्बार का 60% असर बेलारूस में पड़ा था, लेकिन दूर दराज के देशों से भी रेडियोधर्मी असर पड़ने की खबरें आई थी। बहुत बुरी तरह प्रदूषित क्षेत्रों से लगभग 4 लाख लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाया गया। इस प्रदूषण के लम्बे अर्से तक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव अब तक भी सामने आ रहे हैं। बहुप्रचारित इन प्रमुख दुर्घटनाओं के अलावा अनेक छोटे हादसे और भूलें दुनिया भर में न्युक्लियर प्लांटों में हुई हैं अक्सर जिनकी जानकारी सामने नहीं आई है। जापान में इसके साक्ष्य हैं कि उनके द्वारा संचालित न्युक्लियर प्लांटों की असुरक्षित स्थिति को छिपाने के लिए खुद टोकियो इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी (टी.ई.पी.सी.ओ) ने झूठे सुरक्षा आंकड़े पहले भी दिए थे। टीईपीसीओ ने 2002 में स्वीकार किया था कि बहुत अर्सा पहले 1990 में फुकुशिमा दाईची प्लांट के रिएक्टर नम्बर 1, 2, 3, 4 और 5 की कोर के आवरण में जो दरारें दिखाई दी थी, उनके बारे में झूठी खबरें दी गई थी। भारत में भी एटोमिक पावर स्टेशनों में दुर्घटनाएं हुई हैं। भारतीय न्युक्लियर प्रोग्राम में सुरक्षा उपायों का उल्लंघन लगभग मेल्टडाउन, हैवी वाटर रिसाव, टरबाइन-ब्लेड का फेल हो जाना, मोडरेटर प्रणाली में गड़बड़ी, एमरजैंसी कोर कूलिंग प्रणाली का काम न करना, कूलेंट पम्पों में आग लग जाना, ढांचागत विफलताओं से लेकर बाढ़ दुर्घटनाओं तक में पाया जाता है। 1999 में कलपक्कम में हुए हादसे में रेडियोधर्मी हैवी वाटर के छलकने की वजह से सात कर्मचारी भारी रेडियोधर्मिता का शिकार हुए थे। जनवरी 2003 में वहां फिर एक गंभीर हादसा हुआ जब हाई-लेवल रेडियोधर्मी तरल वेस्ट टैंक और एक लो-लेवल तरल वेस्ट टैंक को अलग करने वाले वाल्व में गड़बड़ी हो गई और रिसाव शुरू हो गया था। इसका परिणाम हुआ कि हाई-लेवल रेडियोधर्मी वेस्ट लो-लेवल वेस्ट के साथ मिश्रित हो गया। यह हादसा इतना गंभीर था कि मुख्य प्लांट छः महीने के लिए बंद कर दिया गया। 1993 में नरोरा प्लांट में विनाशकारी आग लगी थी लेकिन कुछ कर्मचारियों की सूझ-बूझ और बहादुरी ने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो यह हादसा दूसरा चेर्नोबिल कांड साबित होता। इस हादसे पर एटोमिक एनर्जी रिगुलेटरी बोर्ड(एईआरबी) की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन 1994 में आई बाढ़ में जलमग्न हो गया था। बाढ़ का पानी टरबाइन बिल्डिंग, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट फेसिलिटी और कॉम्पलैक्स के अन्य हिस्सों में घुस गया था और न्युक्लियर वेस्ट के कनस्तर खुले में तैर रहे थे। किस्मत से जब बाढ़ आई तो प्लांट बंद कर दिया गया था, नहीं तो इसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता। रावतभाटा के प्लांट तो हमेशा ही दरारों और ट्यूब रिसावों आदि से आक्रांत रहते हैं जिससे इतनी संगीन खराबी आ जाती है कि कोई न कोई यूनिट सालों तक बंद करनी पड़ती है। एईआरबी के चेयरमैन डॉक्टर ए. गोपाल कृष्णन ने कहा, ''डीएई चाहता है, सरकार और लोग विश्वास कर लें कि हमारे न्युक्लियर संयंत्रों में सब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं। एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है।'' देश में न्युक्लियर संस्थानों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले 130 से भी ज्यादा न्युक्लियर मुद्दों का उन्होंने संकलन किया है। एईआरबी के अन्य पूर्व चेयरमैन एस.पी. सुखात्मे ने 2001 में हुए एक हादसे के बाद जिसमें एक रिएक्टर से ट्रीटीयम-प्रदूषित कूलेंट लीक कर गया था, चेतावनी दी थी कि जब तक कुछ न्युक्लियर रिएक्टरों के डिज़ाइन को ही जबर्दस्त रूप से सुधारा नहीं जाता है तब तक भारत को आने वाले अनिष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी इस चेतावनी को नजरंदाज कर दिया गया।

सबक जो लेने चाहिएं

जापान के हादसे ने एक बार पुनः दिखा दिया है कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ठीक कब कितनी ताकत के साथ प्राकृतिक आपदा प्रहार करेगी और यह कि इन्सान के पास इस तबाही को नियंत्रित करने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। साधारणतया उद्योगों को सामान्य आपेक्षित तीव्रता की प्राकृतिक घटनाओं का मुकाबला कर पाने के आधार पर निर्मित किया जाता है, लेकिन अधिकतम संभव तीव्रता के लिए नहीं। जापानी प्लांटों को वस्तुतः भूकंपों और सुनामियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाया गया था, लेकिन असल आयाम आपेक्षित सीमाओं को पार कर गया। अक्सर हादसे ऐसे दुष्परिणाम लाते हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फुकुशिमा में रिएक्टर की बिल्डिंग भूकंप और सुनामी के थपेड़े झेल गई थी और एमरजैंसी प्रणाली ने रिएक्टरों को बंद भी कर दिया था लेकिन विद्युत प्रणाली ठप हो गई थी और डीजल बैक-अप सिस्टम भी बैठ गया था जिसके चलते ठंडा करने की प्रणाली फेल हो गई। नतीजतन, ईंधन छड़ें और नियंत्रक छड़ें गर्म होनी शुरू हो गई और रिएक्टर कोर के पिघलने का संभावित खतरा मंडराने लगा। किसी को भी पूर्वाभास नहीं था कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। जापान तकनीकी रूप से बहुत ही विकसित देश है, इसके सुरक्षा मापदण्डों को ग्लोबल न्युक्लियर इंडस्ट्री में सबसे उत्तम माना जाता है और ऐसे हादसों का मुकाबला करने के लिए अति प्रभावकारी मशीनरी उनके पास है। इस मामले में उनकी साख है। इतना होने के बावजूद, जापान में जब ऐसे संकटपूर्ण हालात पैदा हो गए, तो सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना यदि ऐसे किसी देश में घटी होती जिसकी तैयारी इतनी नहीं है तो कितना विनाशकारी प्रभाव हुआ होता।

नाभिकीय विद्युत उत्पादन में खतरा अंतर्निहित है और सही सोच रखने वाले लोगों ने चाहे इंसानी भूल, प्राकृतिक आपदा से हो या डिजाइन की त्रुटि की वजह से या इन सब सबसे मिलकर न्युक्लियर रिएक्टरों में होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर चिंता जताई है। एक जाने-माने पत्रकार और समाज विज्ञानी प्रफुल्ल बिदवई ने फ्रंट लाइन (26 मार्च से 8 अप्रैल, 2011) के लेख में चार्ल्स पेरो की किताब नॉर्मल एक्सीडेंट से उद्धृत किया है कि न्युक्लियर रिएक्टर व्यवस्थित रूप से जटिल और आंतरिक रूप से कस कर जुड़े हुए हैं। एक सब-सिस्टम में हुई खराबी या गड़बड़ी तेजी से दूसरे सब-सिस्टमों में फैल जाती है और बढ़ती रहती है जब तक कि पूरा सिस्टम संकट की दशा में नहीं चला जाता है और यह अक्सर सेकंडों और मिनटों में हो जाता है। ऐसे दृष्टांत हैं जब एक छोटे से हिस्से की गड़बड़ी के चलते अज्ञात और अभूतपूर्व नतीजे सामने आए और उनसे संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। न्युक्लियर पावर स्टेशन में होने वाले हादसों को अन्य औद्योगिक प्लांटों में होने वाले हादसों के समान नहीं समझा जा सकता है। ये अतुलनीय रूप से अधिक विनाशकारी होते हैं और इनका प्रभाव न केवल बहुत बड़े क्षेत्र और यहां तक कि पूरी दुनिया की आबादी पर पड़ता है बल्कि इनका प्रभाव कई पीढ़ियों तक प्रसारित होता रहता है।

हाल ही में एक लेख (द हिन्दू, 11अप्रैल, 2011) में सीएमसी, वेल्लोर के प्रोफेसर के. एस. जैकब ने इस तथ्य की तरफ ठीक ही ध्यान आकर्षित किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में न्युक्लियर टैक्नोलॉजी विकसित हुई और न्युक्लियर एनर्जी सम्बंधी बाद का विकास और नवीनीकरण भी मिलिट्री संदर्भ में ही हुआ। स्वाभाविक है कि जब दुश्मन का करने सफाया करने में न्युक्लियर एनर्जी की क्षमता का संदर्भ आ गया, तब सुरक्षा मुद्दों और इन्सानों पर इसके प्रभाव को महत्वहीन समझा गया। यही नजरिया तब रहा जब विद्युत उत्पादन

(शेष पृष्ठ 7 पर)

जैतपुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की निन्दा की

20 अप्रैल 2011 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के जैतपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे ग्रामिणों पर बिना किसी उकसावे के की गई पुलिस फायरिंग की हम तीव्र निंदा करते हैं, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के खिलाफ ग्रामीण अपने न्यायोचित विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे जो उनके जीवन को गंभीर खतरे में डाल देगा। हम बार-बार जोर देकर कर रहे हैं कि निहित खतरों और इससे जुड़ी तबाही की घोर अवहेलना करते हुए न्युक्लियर पावर जेनरेशन का रास्ता अपनाना और कुछ नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना है और इसलिए सही सोच रखने वाले लोगों के तमाम तबकों द्वारा पूरी शांति के साथ इसका विरोध किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी ऐसे अनिष्टकारी प्रस्तावों का शुरूआत से ही विरोध करती आई है और संगठित जन आन्दोलन के दबाव के तहत पश्चिम बंगाल के हरिपुर में ऐसे एक प्लांट की स्थापना को सफलतापूर्वक रोक सकी थी।

हम जैतपुर के संघर्षशील लोगों की सराहना करते हैं और अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते है और सरकारों से न्युक्लियर पावर जेनरेशन की नीति को तुरंत छोड़ने की माँग करते हैं तथा जैतपुर में न्युक्लियर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव का परित्याग करने का आग्रह करते हैं। हम प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ-साथ मृतक के परिवारजनों और इस बर्बर पुलिस कार्रवाई के चलते गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने की माँग करते हैं।

जनता में जाओ, उनमें रहो, उन्हें संगठित करो, उन्हें आन्दोलन में लाओ और उनको नेतृत्व दो

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण

(रोहतक में 24 अप्रैल के अवसर पर हुई जनसभा में कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती ने जो भाषण दिया उसको यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।)

कॉमरेड सभापति और कामरेड्स,

हम अपनी आदरणीय पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इससे कुछ महीने पहले आपको शायद पता होगा की तमाम यूरोप में, ग्रीस से लेकर इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तक, सभी देशों में मजदूर और मेहनतकश जनता लाखों-लाख की संख्या में लड़ाई में लगी हुई थी। एक तूफान की तरह, आन्दोलन की एक लहर की तरह आगे बढ़ रही थी और उसके बाद ही जिन्हें हम अरब देश कहते हैं मध्य-पूर्व के उन तमाम देशों में, मिस्र से शुरू करके ट्यूनिशिया, लिबिया, अलजीरिया, बहरीन, यमन तक इन सभी देशों में लाखों-लाख की संख्या में लोग आन्दोलन में कूद पड़े थे। इन सभी का तात्कालिक कारण यदि खोजा जाये, तो हम देखेंगे कि जिस तात्कालिक कारण से एक देश में आन्दोलन शुरू हुआ, दूसरे देश में आन्दोलन का तात्कालिक कारण दूसरा होगा, लेकिन यदि और भी गहराई से विचार करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि तमाम देशों के आन्दोलन का जो मूल कारण है, वह एक ही है। वह कारण है पूंजीवादी शोषण और अत्याचारी बुर्जुआ शासन जो पूंजीवाद की ही देन है। यह आन्दोलन उभर कर आ रहा था। इससे लोगों को काफी उम्मीदें थीं। आन्दोलन में वह ताकत भी थी जिससे कि वह पूरे समाज को बदल दे जिसे हम कहते हैं क्रांति हो जाये, सारे देशों में क्रांति हो जाने की स्थिति तैयार हो गई लगती थी, लेकिन हुई नहीं। कुछ माँगें तो जरूर हासिल हो गई, लेकिन क्रांति नहीं हुई। इससे हमें क्या सबक लेना है? इसकी सीख क्या हैं? लेनिन ने जो कहा था उसे पहले मैं अंग्रेजी में कहूँगा, बाद में उसका हिन्दी में अनुवाद भी कर दूँगा। उन्होंने कहा था, " Without a revolutionary theory there will not be revolution." उन्होंने यह भी कहा था, "Without a revolutionary party, there will be no revolution." अर्थात् जैसे क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांति कभी नहीं हो सकती, वैसे ही क्रांतिकारी पार्टी के बिना भी क्रांति नहीं हो सकती। यह इतना बड़ा आन्दोलन, इतनी बड़ी बगावत हुई, लेकिन क्रांति नही हुई। क्योंकि न तो क्रांतिकारी सिद्धांत था और न ही क्रांतिकारी पार्टी थी। यह कोई पहली बार की बात नहीं है? बार-बार ऐसा हुआ है। बहुत देशों में ऐसे आन्दोलन होते रहे, लेकिन क्रांति नहीं हुई। इससे हमें इतना जरूर समझना चाहिए कि हमें अगर क्रांति करनी है, तो यह क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी पार्टी के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सवाल उठ सकता है कि क्रांतिकारी सिद्धांत तो हमारे पास है। कॉमरेड शिवदास घोष क्रांतिकारी सिद्धांत देकर गये हैं। हमारे पास क्रांतिकारी पार्टी भी है जिसकी वे 24 अप्रैल, 1948 को स्थापना करके गये हैं। दोनों ही चीज तो हमारे पास हैं। लेनिन ने जो बताया था कि क्रांति के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी पार्टी होनी चाहिए, ये दोनों ही शर्तें तो पूरी हैं। फिर क्रांति क्यों नही हो रही? इसके लिए एक और चीज जरूरी है जो स्टालिन ने सुन्दर ढंग से बतायी और बाद में कॉमरेड शिवदास घोष ने भी जिसका जिक्र किया वह यह है कि क्रांति करने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी पार्टी तो होनी निहायत ही जरूरी है। ये तो प्राथमिक शर्तें हैं, बुनियादी चीजें है। लेकिन इनसे ही क्रांति नहीं होगी। यह जो राजसत्ता है, जैसे हमारे देश की राजसत्ता है, यह एक भयंकर पूंजीवादी राजसत्ता है। हमारे देश का पूंजीवाद अब साम्राज्यवादी बन गया है, फासीवादी हो गया है। दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में पाँचवे नम्बर की (Fifth position in the world) है। लोग जब क्रांति करने जाएंगे, तो यह लोगों को रोकेगी। क्रांति करने के लिए यह जो फौज है, इसे उखाड़ फेंकना पड़ेगा। राजसत्ता का आखिरकार मतलब होता है फौज। फौज को उखाड़ फेंकने की ताकत अगर न हो, तो क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी पार्टी होने के बावजूद क्रांति नहीं होगी। यह शिक्षा हमें आज लेनी चाहिए।

आन्दोलन चाहे यूरोप में हुआ या अरब देशों में, जिस कारण से यह जो आन्दोलन हुआ उसके मद्देनजर हमारे देश की स्थिति क्या है? यह क्या अच्छी है? बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे पहलुओं में भारत की स्थिति उनसे भी खराब है, लेकिन उस तरह का आन्दोलन नहीं हो रहा है। कुछ-कुछ छिटपुट आन्दोलन यहाँ-वहाँ हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यूरोप में आन्दोलन हुआ, अरब देशों में, मध्यपूर्व के देशों में, मिस्र, ट्यूनिशिया, लिबिया या अन्य सब अरब देशों में हुआ, उस प्रकार का आन्दोलन हमारे देश में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो राजनैतिक पार्टियाँ हैं जिनका प्रभाव आम जनता पर है, वे कौन सी पार्टियाँ हैं? जैसे कांग्रेस को ले लीजिए। वह क्या आन्दोलन करेगी? वही तो पूंजीवाद की सेवा करते हुए जनमत की परवाह न करते हुए तमाम जनविरोधी नीतियाँ अपना रही है। आन्दोलन करना तो दूर की बात रही, जब आन्दोलन होता है, तो वह बेरहमी से आन्दोलन को दबाती है। फिर दूसरी है भारतीय जनता पार्टी जो एक और बुर्जुआ पार्टी है। पूंजीवाद की सेवा करने के लिए दोनों ही एक दूसरी के साथ कम्पीटीशन कर रही हैं। एक दूसरे से बढ़चढ़कर वे टाटा-बिड़ला को दिखा रही हैं कि वह दूसरी पार्टी आपकी क्या सेवा करेगी, उसकी बजाय हम आपकी ज्यादा सेवा करते हैं, हमें अपनाओ। ये पार्टियां क्या खाक आन्दोलन करेंगी? उलटे, ऐसी पार्टियां तो आन्दोलन को दबायेंगी। फिर कौन सी पार्टियाँ बच गई? ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये चाहे बिहार में लालूजी की पार्टी आरजेडी हो या उ.प्र. में मायावतीजी की बसपा हो, या तमिलनाडु में जैसे डीएमके हो या एआईएडीएमके, या आन्ध्र प्रदेश की टीडीपी हो या हरियाणा में चौटालाजी की इनेलो हो, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय बुर्जुआ वर्ग की पार्टियाँ हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वे जनहित के लिए आन्दोलन नहीं करेंगी। बल्कि उलटे, वे पूंजीपतियों के हित के लिए, बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थ के लिए मजदूर आन्दोलन को दबायेंगी, किसान आन्दोलन को दबायेंगी।

इसलिए स्थिति क्या हो गई है? यह इतना बड़ा जो संकट पूंजीपतियों का चला, इससे पूंजीवाद हिल गया था। यह कुछ साल पहले की बात है। इसके बावजूद भारत में जितने भी कारपोरेट घराने हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वे बहुत ही लाभ में हैं। कल मैं कॉमरेडों को अखबार से दिखा रहा था कि तमाम कारपोरेट घराने लाखों करोड़ों रुपये मुनाफा कमा रहे हैं। इस संकट में उनका कोई घाटा नहीं हुआ। तब भी सरकार उनको प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। अर्थात् उन कारपोरेट घरानों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें पैसा दिया जा रहा है। यह किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है, सरकारी खजाने से जनता का पैसा उन्हें दिया गया है। कोई प्रधानमंत्री या वित्तमंत्री अपनी जेब से पैसा उन्हें नहीं देते हैं। वे जनता का पैसा देते हैं। जनता से टैक्स वसूल कर सरकारी खजाने में जो रवेन्यू या राजस्व आता है, उससे पैसा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ऐसा सारी सत्ताधारी पार्टियाँ कर रही हैं। जबकि आप किसानों की स्थिति को ले लीजिए। पिछले दिनों आन्ध्र प्रदेश में एक के बाद एक रोजाना दस-दस किसानों ने आत्महत्या की। इस बार म.प्र. में किसानों की आत्महत्याएं भयंकर रूप में हो रही हैं। आप सोचकर हैरान हो जायेंगे कि पश्चिम बंगाल में जहाँ सीपीआई(एम) की सरकार है, वहाँ मालदा नामक एक जिला है जिसमें सैकड़ों महिलाएँ बेचने के लिए अपने बच्चों को लेकर कतार लगाये बैठी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दशा इतनी बुरी है कि वे उन्हें खिला-पिला नहीं सकती। देखिये क्या हाल कर दिया है कि माँ अपनी सन्तान को बेच रही है। ये तो मैं कुछ चुनीन्दा मिसाल दे रहा हूँ। तमाम देश में यदि देखा जाये, तो देश का बहुत बुरा हाल है। खेत मजदूरों को साल में कई महीने काम नहीं मिलता है। आपके यहाँ तो कुछ काम मिल भी जाता है। आप बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जाइये, वहां इतना भी काम नहीं मिलता है जिससे दो वक्त भरपेट खाना मिल सके। ऐसे में वे अपने लड़के-लड़की को स्कूल-कॉलेज में कैसे पढ़ा पायेंगे। जबकि कानून की किताबों में सब को शिक्षा, राइट टू एज्यूकेशन, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार सब लिखा हुआ है। पर कानून की किताब में खाली लिखने से क्या होता है? मिलेगा कहाँ से? हाल यह है कि लड़का जब बारह साल का हो जाता है, तो उसे नौकरी करनी पड़ती है, उन्हें मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता है, वरना परिवार का गुजर-बसर नहीं होगा। चाय की दुकान पर या ढाबे पर बर्तन धोना आदि कोई भी काम करके उन्हें गुजारा करना पड़ेगा। यह हकीकत है। फिर भी हमारे देश में यूरोप या अरब देशों जैसा जुझारू आन्दोलन नहीं हो रहा है।

हमारे देश में आन्दोलन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां आन्दोलन का माहौल ही नहीं छोड़ा है। आन्दोलन का माहौल खत्म कर दिया गया है। हमारे देश में आन्दोलन करने की मानसिकता को मिटा दिया है। जनमानस में गांधीवाद के प्रभाव के चलते आजादी आन्दोलन में हिंसा-अहिंसा को लेकर एक सवाल तो था ही था, वह जहां एक बात है, वहीं दूसरी यह बात है कि गांधीजी ने कभी आम आदमी का आन्दोलन नहीं चाहा। वे चाहते थे कि खुद भूख हड़ताल पर बैठ जायें और आम लोग जाकर बस उनके लिए तालियाँ बजायें, नारे लगायें और उनकी जयजयकार करें, पर आन्दोलन न करें, जनआन्दोलन हरगिज नहीं हो। वे खुद जेल में जायेंगे और आप लोग नारे लगाते रहें, तालियाँ बजाते रहें, पर आन्दोलन न करें। यह जो मानसिकता है, यह जनमानस में जबरदस्त रूप में रह गयी है। कांग्रेस, बीजेपी, विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां क्योंकि मूलतः बुर्जुआ पार्टियां हैं इसलिए स्वाभाविक है कि वे तो इस बुर्जुआ व्यवस्था अर्थात् इस शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था की ही रक्षा करेंगी। वे आन्दोलन नहीं करेंगी, बल्कि वे पूंजीपतियों के स्वार्थ में जन आन्दोलनों को कुचलेंगी। दूसरी तरफ, जो सब पार्टियाँ मार्क्सवाद का नाम लेकर चलती हैं, उन तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियों, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टियों-सीपीआई, सीपीआई(एम) आदि ने पहले पहल कुछ आन्दोलन किये थे, लेकिन आज इन सब ने भी आन्दोलन करना छोड़ दिया है। सन् 77 से जब सीपीआई, सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा में सत्ता में आ गई, तब से इन्होंने आन्दोलन करना तो दूर की बात रही, आन्दोलन को कांग्रेस से भी ज्यादा क्रूरता से दबाना शुरू कर दिया है। सिंगूर का नाम आपने सुना होगा। हमारी पार्टी ने वहाँ आन्दोलन किया था। नन्दीग्राम की बात आपने सुनी होगी। वहां भी हमारी पार्टी एसयूसीआई(सी) ने आन्दोलन किया था। तब से भारत में यह कहना आम बात हो गई कि हम भी नन्दीग्राम जैसा आन्दोलन करेंगे। वहाँ क्या हुआ था? यह सीपीआई (एम) पूंजीवाद के खिलाफ नहीं बोलती है, यह पूंजीपतियों के खिलाफ बात करती है। जबकि पूंजीवाद एक व्यवस्था है। जहां पूंजीवाद रहेगा, वहां पूंजीपति भी रहेगा। ये पार्टियां पूंजीवाद के खिलाफ नहीं। उनकी क्रांति का जो रास्ता है, जिसे हम क्रांति की रणनीति कहते है वह है जन गणतांत्रिक क्रांति (People's Democratic Revolution),

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कॉ. चक्रवर्ती का भाषण...

(पृष्ठ 3 का शेष)

पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति नहीं। वे कहते है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन वे क्या लड़ाई लड़ेंगे? सिंगूर में, वहाँ के गरीब किसानों की जमीन छीनकर वे हमारे देश के सबसे बड़े पूंजीपति टाटा को देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ नहीं, पूंजीपतियों के खिलाफ वे इस तरह लड़ेंगे!

नन्दीग्राम में 18 हजार एकड़ जमीन छोटे किसानों, मध्यम किसानों के हाथ से छीनकर इण्डोनेशिया के उस कुख्यात कारोबारी सलीम समूह को देना चाहती थी जिसने केमिकल बम बनाकर अमेरिका को दिया था जिसने उसे वियतनाम में जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इतने बदनाम पूंजीपति को, सलीम समूह को जमीन देने की सीपीआई(एम) की बुद्धदेव सरकार ने कोशिश की। हमने जन संगठन बनाकर उसका विरोध किया। सीपीआई(एम)-नीत सरकार ने दमन चक्र चलाकर उस आन्दोलन को दबाया, गोलियाँ चलवायी, यहां तक कि उनके गुण्डों, क्रिमिनलों ने महिलाओं की इज्जत पर हमला किया। ऐसी सीपीआई(एम), सीपीआई में से आन्दोलन करेगी कौन?

जनआन्दोलन आज जरूरी हो गये हैं। पूंजीवाद सिर्फ हमारे देश में हीं नहीं, तमाम दुनिया भर में पूंजीवाद का शोषण चलते-चलते स्थिति इस तरह की हो गई है कि लोगों के पास जीने का और कोई दूसरा उपाय नहीं रहा है। जनता लड़ाई करने पर मजबूर हो रही है। लेकिन जनता चाहे कितना भी आन्दोलन करे, बार-बार हजारों-लाखों की संख्या में आन्दोलन में कूद पड़े, फिर भी वह आन्दोलन सफल नहीं हो पायेगा; आन्दोलन फिर पीछे हट जायेगा यदि वह सही दिशा में न हो। कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार यह दिखाया था कि यदि आन्दोलन सुसंगठित न हो, सही दिशा में न हो और सही नेतृत्व में न हो, तो सफल नहीं हो सकता। यह सही दिशा कौन देगा? आज गौरतलब बात यह है। यह दिशा देने वाली भारत में सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के सिवा और कोई पार्टी नहीं है।

तमाम देशभर में आन्दोलन छेड़े बिना जिन्दगी की किसी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। क्रांति तो बहुत दूर की बात रही, फिलहाल जो समस्याएं, मुद्दे, सवाल जनता के सामने मुँह बाये खड़े हैं उन्हें हल करने के लिए भी आन्दोलन होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी हमारी पार्टी है, हम संघर्षरत हैं। हरियाणा में भी हम आन्दोलन कर रहे हैं। जहाँ तक सम्भव है हम अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। यह आन्दोलन करना कहाँ तक सम्भव होगा यह हमारी पार्टी की ताकत का सवाल है। आज यह बात हमें समझनी चाहिए। यह एक वास्तविक सीमाबद्धता है। इस सीमा को हमें तोड़ना है ताकि हमारी शक्ति बढ़े। हम जल्दी से जल्दी इसे बढ़ायेंगे। कैसे?

चिन्तन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एक नये चिन्तन, नई संस्कृति को अपनाना होगा जो मजदूर की क्रांतिकारी संस्कृति होती है। व्यक्तिवाद से लड़ते हुए सामूहिकतावाद के आधार पर यह सर्वहारा संस्कृति निर्मित होती है। जैसे कि कॉमरेड शिवदास घोष ने सिखाया था कि मजदूर वर्ग के स्वार्थ के साथ, क्रांति के स्वार्थ के साथ, पार्टी के स्वार्थ के साथ अपने खुद के स्वार्थी को विलीन कर देना, एकात्म कर देना है। यह जो संघर्ष है, इससे इन्सान ताकतवर होता है, इसके बिना नहीं। जब उसके पास ज्ञान नहीं होता है, तो इंसान बहुत कमजोर होता है और जब इन्सान ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, तो वह इतना ताकतवर हो जाता है कि वह दुनिया को बदल दे सकता है, वह नई सभ्यता की सृष्टि कर दे सकता है जैसे लेनिन-स्टालिन ने की थी, जैसे माओ त्से-तुंग ने की थी, हो ची मिन्ह, फिडल कास्त्रो आदि ने की थी। कोई एक व्यक्ति करता तो हम कह सकते थे कि उन्होंने इत्तफाक से ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह प्रमाणित हो गया है कि हम भी कर सकते हैं। यदि लेनिन कर सके, यदि स्टालिन कर सके, यदि माओ त्से-तुंग कर सके, यदि हो ची मिन्ह कर सके या फिडल कास्त्रो कर सके, तो हम भी कर सकते हैं। यह सिद्धांत अर्थात् मार्क्सवाद का ज्ञान कहां से आया है। सिर्फ समाज की ही नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति और जीवन की धारणाओं अर्थात् हर क्षेत्र की धारणाओं को समन्वित-संयोजित करते हुए वैज्ञानिक आधार पर जो ज्ञान आया वह मार्क्सवाद कहलाया। हर क्षेत्र के ज्ञान को संयोजित करते हुए जो महान शिक्षा कार्ल मार्क्स ने दी थी वह मार्क्सवाद हमारी शिक्षा का आधार है। यदि उसे हम समझें, ज्ञान को यदि हम हासिल करें और जीवन में उसे लागू करें, तो वह ज्ञान क्रियाशील ज्ञान हाता है।

कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार यह दिखाया है कि जनता में जाओ, शोषित जनता के पास रहो, शोषित जनता के जीवन की समस्याओं को जानने का प्रयास करो, उन्हें संगठित करो, उन्हें आन्दोलन में लाओ, उनको नेतृत्व दो। इसलिए हमें जनता में जाना है, जनता की समस्याओं को जानना-समझना है, जनता को संगठित करना है, जनता को आन्दोलन में लाना है, जनता को नेतृत्व देना है। यदि हर कॉमरेड इस प्रकार से सोचे, तो जल्द ही पार्टी बढ़ जायेगी। तभी इस सीमाबद्धता को दूर करना सम्भव होगा। यह जो सीमित शक्ति है इसे बढ़ाना तभी सम्भव है। यह आज सबसे जरूरी है। इसलिए कॉमरेड, देखिए समाज में उथल-पुथल मची हुई है, समाज में भयंकर संकट ने जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं है, बल्कि राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक हर क्षेत्र में संकट व्याप्त है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें संकट की काली छाया न हो। इस संकट के चलते जीवन आगे नहीं चल पायेगा। ये जो इस प्रकार की समस्याएँ हैं, वे तो हैं ही अब उनके साथ भ्रष्टाचार और जुड़ गया है। इसने आज विकराल रूप ले लिया है। यह भयंकर रूप से फैल गया है। सत्ताधारी पार्टियों में ऐसा नेता बताना मुश्किल हो गया है जो भ्रष्टाचार में फंसा न हो। किसी का पता चल गया, किसी का नहीं, बस इतनी बात है। ए. राजा के 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त होने के बारे में आपने सुना होगा। उसने एक-दो करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 1लाख 76 हजार करोड़ रुपये हड़प लिये। ऐसे और भी हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री विलास राव पर, कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री यदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ। और भी कितने घपले हुए हैं उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जब व्यवस्था प्रतिक्रियावादी हो जाती है, तब वह मरणासन्न हो जाती है। एक दिन वह व्यवस्था लाजिमी तौर पर प्रतिक्रियावादी और मरणासन्न होगी ही। क्योंकि कोई भी चीज जो चाहे समाज में हो या प्रकृति में हो या जीवन में हो, जब आती है, तो वुछ दिन तक इतिहास में एक प्रगतिशील भूमिका रखती है। वह विकसित होती है, विकसित होते-होते एक चरम अवस्था में पहुँचकर उसका पतन होना शुरू हो जाता है। एक नयी सत्ता को जन्म देते हुए उसे एक दिन अस्तित्व से चले जाना होता है। हर चीज ऐसे बदलती जा रही है। बदलते-बदलते वह चीज दुनिया से जा रही है, उसकी जगह नई चीज आ रही है, फिर नई चीज भी बदलते-बदलते पुरानी हो जाती और उसे भी चले जाना पड़ता है, यह प्रकृति, समाज, जीवन, हर क्षेत्र का, सारे वस्तुजगत का ही नियम है, उसी के चलते यह पूंजीवाद आज पुराना हो गया है। आज से 100 साल पहले लेनिन ने मार्क्सवाद के विचार से ही दिखाया था कि जब पूंजीवाद विकसित होते हुए अपने इस चरम स्तर, साम्राज्यवादी स्तर में आया, तो यह इसके चरम विकास का स्तर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके बाद इसके और विकास की और कोई गुंजाइश नहीं रही है, इसका पतन होगा ही। लेनिन ने दिखाया था कि 1902-03-04 के आसपास विश्व पूंजीवाद साम्राज्यवादी स्तर पर पहुंचने के बाद मरणासन्न हो चुका है, प्रतिक्रियावादी हो चुका है। ऐसा हुए सौ साल हो गये हैं। फिर भी पूंजीवाद तो रह ही गया है। इससे तो बीमारी फैलेगी ही। जब कोई बुढ़ा होकर बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने पर न केवल खुद ही दुख भोगते हैं, बल्कि बीमारी फैलाते भी हैं। उन्हें चले जाना होता है। जब नहीं जाते हैं, तब ऐसा होता है, लेकिन जैसे प्रकृति में परिमाणगत परिवर्तन होते-होते प्राकृतिक नियम से अपने आप गुणगत परिर्वतन हो जाता है, समाज में ऐसे नहीं होता है, खासकर शोषणमूलक समाज में जिसमें पूंजीपति शोषक-शासक हैं और मजदूर व मेहनतकश जनता, आम आदमी शोषित-शासित हैं, समाज में ये जो दो विरोधी शक्तियाँ हैं, उनके बीच संघर्ष है, इसमें परिर्वतन अपने आप स्वत:स्फूर्त नियम से नहीं होता है। हम जहाँ आन्दोलन के लिए, क्रांति के लिए अनुकूल परिवेश तैयार कर रहे हैं, वहीं पूंजीपति वर्ग उसी तरह आन्दोलन या क्रांति को रोकने के लिए प्रतिकूल परिवेश तैयार कर रहा है। ये जो टेलिविजन में इतने गंदे विज्ञापन आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही मरणासन्न समाज में सांस्कृतिक स्तर का पतन हो रहा है, ऊपर से इन गंदे विज्ञापनों, शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देकर आम आदमी, खासकर नौजवानों का सांस्कृतिक पतन, चारित्रिक पतन लाने के शासक पूंजीपति वर्ग के प्रयास जारी हैं। वे चाहते हैं कि जनता, खासकर नौजवान कोई गहन चिन्तन-विचार न कर सकें, इसलिए वे एक हल्का-छिछला सा माहौल(Light atmosphere) तैयार कर रहे हैं कि 'खाओ पीओ मौज करो'। शराबखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा-पंजाब में दो-दो कदम पर शराब की दुकान हैं। सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि केरल में स्कूली बच्चों, 12-12 साल के बच्चों के पास से शराब की छोटी-छोटी बोतलें बरामद हुई हैं। उन्हें शराब पीने की लत लग चुकी है। 'शराब पीओ, पीओ, खूब पीओ, मौज-मस्ती में डूबे रहो और दुनिया भूल जाओ' - यह जो माहौल है यह क्या है?

पूंजीवाद में ऐसे ही चारित्रिक पतन होता रहता है, उसमें यह भी जुड़ गया है। यह सब जायेगा कैसे? यह अन्ना हजारे का जो आन्दोलन आपने देखा है जिसका हमने समर्थन किया। यह ठीक है कि हमने इस आन्दोलन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने आन्दोलन को आगे बढ़ने नहीं दिया। जनता में विक्षोभ है, उन्होंने पूरे भारत भर में इस मुद्दे को उठाया जरूर, लेकिन आन्दोलन आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने इसका अंधा समर्थन नहीं किया। देखिये उन्होंने क्या किया? जो आन्दोलन होने की उम्मीद थी, आन्दोलन आगे चलने की जो सम्भावना थी, उन्होंने उस सम्भावना पर पानी फेर दिया। वे आन्दोलन को गलत रास्ते पर ले गये। वे ऐसा करेंगे ही क्योंकि वे क्या कोई क्रांतिकारी हैं जो कोई आन्दोलन करेंगे। उलटे, आन्दोलन को उन्होंने मिटा दिया। आन्दोलन को कानून बनाने की अंधी गली में फंसा दिया। आज बिल बना रहे हैं, जन लोकपाल बिल बनेगा। इससे क्या होगा? बिल अगर संसद में पास हो गया, तो कानून बनेगा। कानून तो पहले भी बहुत हैं। दुनिया में ऐसा कोई अपराध आप बता नहीं सकते हैं जिस पर हमारे देश में कोई कानून न बना हो। इण्डियन पेनल कोड आप यदि पढ़ें, तो आपको पता चल जायेगा कि तमाम अपराधों के खिलाफ कानून लिखे हुए हैं। उससे क्या अपराध घटे हैं? बल्कि उलटे, अपराध बढ़े हैं, खास कर महिलाओं पर होने वाले अपराधों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। महिलाओं की इज्जत दिन-दहाड़े लूट ली जाती है। पहले तो बलात्कार करके छोड़कर चले जाते थे, अब बलात्कार करके जान से मार देते हैं। इतने बड़े-बड़े कानून के पोथे हैं, सब धाराएं

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कॉ. चक्रवर्ती का भाषण...

(पृष्ठ 4 का शेष)

लिखी हैं, अदालत है, एडवोकेट हैं, जज हैं, कानून को लागू करने के भी सारे बन्दोबस्त हैं, सब कुछ है लेकिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए कानून बनाकर आप भ्रष्टाचार को मिटायेंगे, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। कानून बने इतने दिन हो गये, अब तक सब अपराध खत्म हो गये होते।

एक और भी बड़ी बात है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, इसे मिटाने के लिए एक नई संस्कृति चाहिए। व्यक्तिवाद को आधार करके पुरानी सड़ी-गली संस्कृति, पुराना चिन्तन, पुरानी एथिकल धारणाएँ अर्थात् नीति-नैतिकता, ईमानदारी यह जो पुरानी पूंजीवादी धारणाएं है, उनकी जो चेतना है, जो मूल्यबोध हैं, नीति-नैतिकता की जो धारणाएं आयी हैं, जो संस्कृति आयी है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है निजी सम्पत्ति। प्राइवेट पोप्रटी है उसका आधार। तब जब निजी सम्पत्ति बनाने के चिन्तन ने आज इतना भंयकर रूप ले लिया है और नौकरियां हैं नहीं, दिन-ब-दिन नौकरियों की संख्या घटती जा रही हैं, इससे यह अनिश्चतता मन में घर कर गई है कि भविष्य में न जाने क्या होगा, हमारे लड़के का क्या होगा, पता नहीं उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। इस डर से, इस आशंका से उनकी कोशिश है कि जितनी ज्यादा सम्पत्ति बढ़ायी जा सके, बढ़ायी जाये। इस प्रकार के चिन्तन से तो भ्रष्टाचार(क्रप्शन) आयेगा ही। सम्पत्तिबोध जितना गहरा होता जायेगा, जो आज हो रहा है, भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है तथा यह और भी बढ़ेगा। अन्ना हजारे क्या इससे लड़ सकते हैं? इससे लड़ने के लिए जो संस्कृति चाहिए, जो नीति-नैतिकता होनी चाहिए वह है व्यक्तिगत सम्पत्ति को छोड़ देना, सिर्फ व्यक्ति सम्पत्ति ही नहीं, बल्कि कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति जनित जो मानसिकता है(Private Property Mental Complex) उससे लड़ना होगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति से जो मानसिकता पैदा होती है, उससे मुक्त होना होगा। वह होती है कम्युनिस्ट कल्चर। यह नई संस्कृति जो नहीं ला पायेगा, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन को नेतृत्व नहीं दे पायेगा और सही रास्ता भी नहीं दिखा पायेगा। आखिरकार इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर ही इस भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। लेकिन तब तक क्या हम आन्दोलन नहीं करेंगे? हाँ हम आन्दोलन करेंगे। इसके खिलाफ एक नई संस्कृति को आधार करके एक मानसिकता तैयार करनी होगी वरना आप इससे लड़ नहीं पायेंगे।

समाज में भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ जमा ली हैं। ट्रेन से जाना है, रिजर्वेशन है नहीं और टीटी कहता है कि सीट चाहिए, तो पैसा दो। लोग यह सोचकर कि क्या करें जल्दी जाना है इसलिए पैसा दे देते हैं। आर्डिनरी आदमी यह सोचते भी नहीं हैं यह भ्रष्टाचार है। आम आदमी भी इसमें फंस गये हैं। वे तर्क देते हैं कि क्या करते, जल्दी जाना था, इसलिए पैसा देना पड़ा। सरकारी कार्यालय में या स्कूल-कॉलेज में रेट बंधा हुआ है कि ट्रांसफर के लिए इतना देना पड़ेगा- किसी के लिए 5 लाख रु., किसी के लिए दो लाख रु., बड़े अफसर के तबादले के लिए 10 लाख रुपये। ऐसा बिल्कुल दस्तूर बना हुआ है। बिना पैसा दिये काम बनेगा ही नहीं। 'अच्छा रिश्वत दे दो'-आलम ये हो गया। आम जनता को भी इसमें फंसा दिया है। ऐसे में, आप बखूबी समझ सकते हैं कि देश में कितने बड़े आन्दोलन की जरूरत है और कितनी ऊंची संस्कृति के आधार पर यह आन्दोलन होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मानसिकता तैयार हो जाये, जिससे कि ऐसा भ्रष्टाचार करने से भ्रष्टाचारी डरें। आन्दोलन के जोर से उन्हें समाज से एकदम अलग-थलग कर दिया जायेगा। चोरों की तरह उन्हें भी हम समाज से अलग-थलग कर दे सकते हैं। ऐसा एक माहौल और एक आन्दोलन तैयार करना अन्ना हजारे ही क्यों, इस तरह के चिंतन को लेकर चलने वाला चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, भले ही वह ईमानदार हो, उसके लिए ऐसा आन्दोलन करना सम्भव नहीं है। वे तो एक गांधीवादी हैं। वे कहते हैं कि पार्लियामेन्ट कानून बनाये तब भी ठीक है और नहीं बनाये तब भी ठीक है। तब फिर कानून बनवाने के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं? कॉमरेडो, यह हमें समझना चाहिए कि इस आन्दोलन में सही नेतृत्व सिर्फ हम ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। इसका क्या यह मतलब हुआ कि उन्हें हम समर्थन नही देंगे। नहीं, यह बात नहीं है। जब कोई आन्दोलन आया है और कोई आन्दोलन में है, अर्थात् जनवादी आन्दोलन में है, तो हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन उसमें हमारा यह सोचना ठीक नहीं है कि आँख बंद करके समर्थन देंगे। हमने इस आन्दोलन का समर्थन इसलिए किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन होना चाहिए, लेकिन वह आन्दोलन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका भी जिक्र केन्द्रीय कमेटी के उस बयान में है, आप देखिये।

पूंजीवाद ही इस भ्रष्टाचार को पैदा कर रहा है। पूंजीवाद-विरोधी चिन्तन के बिना यह दूर नहीं हो सकता। पूंजीवाद-विरोधी संस्कृति से ही भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करना सम्भव है। यह हमारी पार्टी के बिना और कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी पार्टी के अलावा और किसी पार्टी ने पूंजीवाद-विराधी रास्ता चुना नहीं है। तब आज की स्थिति में जब हजारों समस्याएं हैं, उनके सामने हम क्रांतिकारी पार्टी और क्रांतिकारियों को क्या करना चाहिए? हम क्या महज देखेंगे, क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर देखते रहेंगे, या जनता में जाकर, जनता को संगठित करते हुए तमाम देशभर में आन्दोलन गठित करेंगे। यह एक विशाल देश है। हरियाणा को ही संगठित करना कितना कठिन है, यह आप जानते हो। ऐसी बहुत सारी जगह बची है जहाँ हमारी पार्टी अभी है नहीं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पार्टी अभी छोटी है। लेकिन आम जनता को जुटाना है। कैसे? जितनी ताकत है, उसको लेकर यदि हम आन्दोलन शुरू कर दें और जुझारू लड़ाई हो, जिसको लोगों की नजरों से औझल नहीं रखा जा सकेगा, जिसकी खबर फैलती जायेगी, जैसे सिंगूर या नंदीग्राम में हुआ उस प्रकार का जनता का आन्दोलन जब हम करेंगे, एक छोटी सी जगह पर होने पर भी इसका प्रभाव तमाम देश भर में होगा। उससे लोग प्रोत्साहित होंगे, उनका हौंसला बढ़ेगा, वे आन्दोलन में जुटेंगे। आन्दोलन का एक माहौल जो इन सभी पार्टियों के आचरण से खत्म हो चुका है, हमें आन्दोलन का वह माहौल तैयार करना है। एक नई संस्कृति, एक नये विचार, एक नये चिन्तन, एक नये सिद्धांत, एक नये रास्ते को आधार करके यह आन्दोलन शुरू करना है, जिसकी रोशनी पाकर लोग प्रोत्साहित होंगे, जनता में इस आन्दोलन की खबर बहुत दूर तक फैल जायेगी। जनता आन्दोलन चाहती है। हम क्या उनको प्रत्युत्तर नहीं देंगे? यह सवाल आज 24 अप्रैल बार-बार हमसे करता है। इसके लिए जो कदम उठाना है, वह यदि हम उठा सके, तो क्रांति बहुत दूर नहीं है, यह मैं अपनी तमाम जिंदगी के संघर्ष के तजुर्बे से कह रहा हूं। क्रांति ज्यादा दूर नहीं है। जब हरियाणा में पार्टी का काम शुरू हुआ, उन दिनों यहां पार्टी का संगठन क्या था और आज पार्टी कितनी बढ़ गई है। तमाम भारत में बहुत जगह पार्टी थी ही नहीं, लेकिन वहां भी पार्टी बन चुकी है और अब पार्टी बढ़ रही है। जहाँ भी कॉमरेड शिवदास घोष के चिन्तन को हम ले जा पाये, वहीं जनता इसके प्रति आकर्षित होकर आ रही है।

कॉमरेड शिवदास घोष की विचारधारा को आप गहराई से जानें, विचार करें, आपस में चर्चा करें, कॉमरेडों-कॉमरेडों में चर्चा करें, ज्ञान का विकास करें, ज्ञान ही शक्ति है, वरना लेनिन कोई इतने लम्बे-तगड़े आदमी नहीं थे, बल्कि वे छोटे से कद के थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि तमाम दुनिया को बदल कर रख दिया। वह ज्ञान चाहिए। वह ज्ञान है जीवन का ज्ञान, समाज, प्रकृति, जीवन, तमाम वस्तु जगत के परिर्वतन के नियमों का ज्ञान। वह ज्ञान विकसित रूप में कॉमरेड शिवदास घोष ने हमें दिया, खासकर भारत में मजदूर वर्ग की मुक्ति का रास्ता कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया। उसे जानें। आज के 24 अप्रैल के इस अवसर पर यही है कॉमरेडों का मकसद। मुझे उम्मीद है, विश्वास है और पूरा भरोसा है कि आप सब इस प्रकार से सोचेंगे और इस संघर्ष को चलायेंगे-खुद को बदलने का संघर्ष छेड़ेंगे। मैं खुद को बदलकर ही दुनिया को बदल सकता हूँ। यदि मैं नहीं बदला, मैं पुराना ही रही गया पूंजीवादी, बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ चिन्तन और आचरण लेकर बैठा हुआ हूं और दुनिया बदल दूंगा - यह कभी नहीं हो सकता। दुनिया को बदलने की पहली शर्त है पहले खुद को बदलना। मार्क्स ने मजदूर वर्ग को पहली शिक्षा दी थी, वह यह है। उन्होंने दिखाया था कि मजदूर दुनिया को बदलेंगे क्योंकि मजदूर वर्ग ही उस निजी सम्पत्ति से मुक्त है जिस निजी सम्पत्ति के कारण ही एक दिन यह समाज वर्ग-विभाजित हो गया था। यह वर्ग-विभाजन कब मिटेगा? यह तब मिटेगा जब निजी सम्पत्ति चली जाएगी और निजी सम्पत्ति को मजदूर ही हटा सकते हैं। क्योंकि मजदूर की संस्कृति है सामूहिकतावाद। वे सामूहिक रूप से उत्पादन करते हैं और समूह के लिए, समाज के लिए करते हैं, इसलिए वे लोग ही उत्पादन के तमाम साधनों पर सामाजिक मालिकाना ला सकते हैं। पूंजीवाद निजी मालिकाना पर चलता है। उत्पादन के तमाम साधनों पर निजी मालिकाना ही पूंजीवाद का आधार है। इस व्यवस्था में दुनिया के कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हाथों में तमाम सम्पत्ति आ जाती है, जैसे आज आ गई है। यह उनसे छीननी है और सामाजिक मालिकाना कायम करना है। इस सामाजिक सम्पत्ति पर वे कुण्डली मारे बैठे हैं। उनको उखाड़ फेंक कर समाज का मालिकाना सिर्फ मजदूर ला सकते हैं। लेकिन मजदूर यह केवल तभी कर सकते हैं जब मजदूर खुद को बदल लें। "Workers can change the world but to change the world they will have to change themselves first" दुनिया को बदलने से पहले उनको खुद को बदलना होगा। हम यदि ऐसे बदलें, व्यक्तिवादी सोच-समझ, चिन्तन को छोड़कर सामूहिक चिन्तन, सामाजिक चिन्तन को अपना लें, दुनिया की समस्याएँ यदि हमारी अपनी समस्याएँ हो जायें तभी हम लेनिन जैसे हो सकते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। हम कहेंगे, खासकर उनसे जो नौजवान कॉमरेड हैं कि सबको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हम भी महान हो सकते हैं, हम भी विकास करके एक दिन महान क्रांतिकारी बन सकते हैं, अगर हम व्यक्तिवाद से संघर्ष करें, व्यक्तिवाद को शिकस्त देते हुए, अपने खुद के स्वार्थ को वर्ग, क्रांति व पार्टी हित के साथ एकात्म करने की जो लड़ाई है उसे तहेदिल से करें, ईमानदारी से करें, लगन के साथ करें, तो महान क्रांतिकारी हो सकते हैं। मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन बनें या न बनें यह बात नहीं है, पर उनके रास्ते से हम यदि संघर्ष करें, तो उनके नजदीक जरूर पहुँच जायेंगे। यही है समय की पुकार। इतना कहकर इस अवसर पर सभी कॉमरेडों को क्रांतिकारी अभिनन्दन देते हुए और हमारे महान शिक्षक, पथ प्रदर्शक व नेता कॉमरेड शिवदास घोष को लाल सलाम देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

इन्कलाब जिन्दाबाद!
एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) जिन्दाबाद!
सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष
लाल सलाम!

24 अप्रैल-पार्टी स्थापना दिवस...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रोहतक में 24 अप्रैल को सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

इलाहाबाद : सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर ममफोर्डगंज के राष्ट्रीय शिशु विद्यालय में सायं 5 बजे एक सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता पार्टी की राज्य समिति के सदस्य और प्रतापगढ़ ज़िला सचिव कॉ. बेचन अली रहे। अध्यक्षता कॉ. एस. मालवीय ने की। सभा में बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया।

कॉ. बेचन अली ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास को रखते हुए कहा कि एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) ही भारत भूमि पर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उच्च नीति-नैतिकता के झण्डे को अपने निर्माण काल से ही उठाये हुए आज भी बढ़ रही है। पूंजीवाद के इस प्रतिक्रियावादी दौर में जहां सभी पार्टियों ने जनता के संघर्ष और जनान्दोलन के रास्ते को छोड़ दिया है तथा संसदीय राजनीति के गर्त में जा फंसी हैं, वहीं कॉमरेड शिवदास घोष के अथक संघर्ष से निर्मित एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) पार्टी नन्दीग्राम से लेकर लालगढ़, जहां कहीं भी संभव है, जनान्दोलन के परचम को बुलन्द किये हुए है।

सभा की अध्यक्षता करते हुए कॉ. एस. मालवीय ने देश की वर्तमान दुखद आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों की विस्तार से चर्चा करते हुए महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा आदि की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने नंदीग्राम के किसानों के गौरवशाली आन्दोलन की मिसाल देते हुए आम जनता विशेष रूप से छात्र-नौजवानों से वर्तमान निराशा-हताशा की स्थिति से बाहर आकर शक्तिशाली और जुझारू जनान्दोलन तैयार करने हेतु उठ खड़े होने का आह्वान किया।

इसके अलावा सभा को कॉ. झरना मालवीय तथा कॉ. राजवेन्द्र सिंह ने भी सम्बोधित किया। संचालन कॉ. सुमनलता शुक्ला ने किया।

गुजरात: गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, आहवा और भुज जिले के भचाऊ में पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया।

23 अप्रैल को अहमदाबाद में पार्टी स्थापना दिवस पर हिमवन पालडी में सभा हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉमरेड जयेश पटेल ने की। पार्टी के राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्यों, कॉ. भाविक राजा व मीनाक्षी जाशी ने सभा को संबोधित किया। मुख्य वक्ता थे पार्टी के राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. द्वारका नाथ रथ।

24 अप्रैल को बड़ौदा, तरासली में जनसभा हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. प्रो. भरत मेहता ने की। मुख्य वक्ता कॉ. मीनाक्षी जोशी थी। अन्य वक्ता थे राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. भारती परमार, मुकेश सेमवाल (ऑल इण्डिया डीवाईओ के) और कॉ. अभिलाष सिंह ने भी सम्बोधित किया।

अहमदाबाद में 24 अप्रैल को सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉ. द्वारिका नाथ रथ

25 अप्रैल को सूरत में पार्टी कार्यालय हाल में सभा हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के सूरत जिला सचिव कॉ. राम भरत मौर्य ने की। मुख्य वक्ता थे पार्टी के राज्य सचिव कॉ. द्वारिका नाथ रथ। ऑल इण्डिया डी वाई ओ के राज्य सचिव कॉ. सत्येन्द्र सिंह और कॉ. राम मूर्ति मौर्य ने भी सभा को संबोधित किया। 17 अप्रैल को भचाऊ में और 26 अप्रैल को आहवा में हुई सभाओं का राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. तपन दासगुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया।

राँची(झारखण्ड) : 24 अप्रैल को पार्टी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसयूसीआई(सी) झारखण्ड ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रांची में राजभवन पर प्रदर्शन किया। जुलूस सैनिक मार्केट से शुरू हुआ। विभिन्न माँगों को लेकर और केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों मुख्यत: पानी की किल्लत, महँगाई, भ्रष्टाचार, झुग्गी झोपड़ियाँ को बुलडोजर चलाकर ढहाने के विरोध में और सीएनटी एक्ट रद्द करने, झारखण्ड को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने, झुग्गी बस्तियों में बेदखली मुहिम को तुरन्त रोकने और इन इलाको के लोगों को इस जमीन का मालिकाना देने के नारे लगाये। जुलूस में 500 से ऊपर पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड हेम चक्रवर्ती ने जुलूस के बाद हुई विरोध सभा की अध्यक्षता की। सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तमाम समस्याओं का मूल कारण यह मरणासन्न पूंजीवाद है। उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार की जनविराधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने का सबसे आह्वान किया। सभा के मुख्य वक्ता राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉमरेड रॉबिन समाजपति ने कहा कि एक तरफ सरकार हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ाते हुए बेचारे गरीब मासूम लोगों के आश्रय स्थलों को बुलडोजर चलाकर मटियामेट कर रही है, दूसरी तरफ अमीरों और ताकतवर लोगों के पक्ष में उनकी सम्पत्तियों, जमीन-जायदाद को बचाने के लिए

ऑर्डिनेन्स ला रही है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के इस आन्दोलन का हम समर्थन करते हैं जो पिछले 6 साल से राज्य में बुलडोजर चला कर बस्तियों को ढहाने की सरकार की इस मुहिम का विरोध कर रही है और उस जमीन पर वहाँ के बासिन्दों को मालिकाना हक देने की माँग कर रही है। राज्य में पानी की मौजूदा किल्लत के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात जैसे राज्य में जहाँ हमारे राज्य के मुकाबला औसत वर्षा लगभग आधी है सरकार ने जल संरक्षण की रणनीति अपनानी है। इसलिए वहाँ लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है; लेकिन हमारे राज्य में ऐसी कोई रणनीति न अपनाने की बदौलत हालत दिन-ब-दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम इन सब जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना होगा। अंत में कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह, सुमित राय, मिली दास व के.पी. सिंह समेत एक प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके निजी सचिव को 9 सूत्री माँगों को पेश करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि–1. पानी की किल्लत दूर करने के लिए गम्भीर प्रयास किये जायें, 2. बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाये और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाये; 3. बीपीएल सूची में गलतियों, विसंगतियों, नरेगा, इन्दिरा आवास व अन्य स्कीमो में भ्रष्टाचार दूर किया जाये; हर आदमी को राशन का प्रबन्ध किया जाये; 4. राज्य को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाये, फसल बीमा फण्ड तुरन्त वितरित किया जाये; 5. सीएनटी एक्ट रद्द करने की साजिश तुरन्त बंद की जाये,7. आवश्यक चीजों की वर्तमान महंगाई के मद्देनजर मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर इस राज्य में कम से कम 250 रु. प्रतिदिन किया जाये। मजदूरों की ले ऑफ, छंटनी बंद की जाये और उन्हें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी व अन्य सुविधाएं प्रदान की जायें, 7. विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में अध्यापकों की कमी तुरन्त दूर की जाये, शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य लेने बंद किये जायें और छात्रों की भलाई के लिए समेस्टर प्रणाली खत्म की जाये, 8. बेरोजगारों को काम दिया जाये तब तक पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाये; 9. महिलाओं पर अत्याचार बंद किये जाये, शराब की दुकानों के लाइसेन्स देने बंद किये जायें।

बुढ़लाडा(पंजाब): 30 अप्रैल को यहां एसयूसीआई(सी) स्थापना दिवस पर हुई सभा की अध्यक्षता पार्टी के पंजाब सूबा इंचार्ज कॉ. अमीन्दरपाल सिंह ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना वैचारिक स्तर ऊंचा उठाने और जन आन्दोलनों को उनकी तार्किक परिणति पर पहुँचाने के लिए उनमें सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। मंच संचालन कॉ. इन्दर सिंह ने किया।

मुरादाबाद(उ.प्र) : 24 अप्रैल को यहाँ प्रेस क्लब भवन में जनसभा की गयी। सभा की अध्यक्षता का. शील कुमार ने की। मुख्य वक्ता पार्टी के प्रान्तीय सचिव कॉ. वी.एन. सिंह थे। सभा का संचालन कॉ. हरकिशोर सिंह ने किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए का. विजय कुमार ने कहा कि आज जो चारों ओर हर क्षेत्र में पतनशीलता दिखाई दे रही है, यह मरणासन्न पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। अत: इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना वक्त की जरूरत है। पार्टी गठन के कॉ. शिवदास घोष द्वारा किये गये संघर्ष का जिक्र करते हुए कॉ. वी. एन. सिंह ने कहा कि उस वक्त देश में सही कम्युनिस्ट पार्टी ने होने के कारण आजादी आन्दोलन में जनता की कुर्बानियों का सारा फल देश के पूजीपतियों ने हड़प लिया। 1947 में समझौते के जरिए देश को विदेशी साम्राज्यवादी शासन की गुलामी से तो आजादी मिली लेकिन शोषण बदस्तूर जारी रहा। इसलिए सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष ने यहाँ पूजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति करने के लिए सही साम्यवादी पार्टी एसयूसीआई (सी)निर्मित की जो अब 22 प्रातों में फैल चुकी है। उन्होने पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। सभा में मौ. इस्लाम, महेन्द्र सिंह देवराज सिंह, मौ. गौरी, एस.एन.सिंह, यशपाल सिंह, एस.पी. सिंह, कमलेश आदि भी मौजूद रहे।

भोपाल(म.प्र.): 24 अप्रैल, एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) का 63वां स्थापना दिवस 28 अप्रैल को राजधानी भोपाल में राज्य स्तर पर मनाया गया। सभा में मुख्य वक्ता केन्द्रीय समिति के सदस्य कॉमरेड सत्यवान थे। उन्होंने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि

(शेष पृष्ठ 8 पर)

जापान में तबाही...

(पृष्ठ 2 का शेष)

के शांति पूर्ण उद्देश्य के लिए न्युक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया गया और संभावित हादसों और खतरों को जरूरी तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा मिलिट्री संदर्भों में बरती जाने वाली गोपनीयता का विस्तार सिविल क्षेत्र के न्युक्लियर पावर जेनरेशन तक कर दिया गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि जोखिम से संबंधित मुद्दों, सुरक्षा उपायों के उल्लंघनों और छोटे-मोटे हादसों इत्यादि को अक्सर दबा दिया जाता है।

फुकुशिमा हादसे के बाद लोगों के दबाव की वजह से ज्यादातर देशों की सरकारों ने अपने न्युक्लियर पावर प्रोग्रामों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। ब्रिटेन, फिनलैंड, चीन तथा बुल्गेरिया ने न्युक्लियर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने को कहा है। इटली और स्वीट्जरलैंड ने नए रिएक्टरों की योजनाओं को स्थगित कर दिया है तथा वेनेजुएला ने न्युक्लियर पावर जेनरेशन की योजनाओं को रद कर दिया है। अमेरिकी सैक्रेट्री ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने न्युक्लियर पावर से जुड़े खर्चों और खतरों पर चिन्ता जाहिर की है। जर्मनी में भी न्युक्लियर रिएक्टरों के एक कट्टर समर्थक चांसलर एंजेला मर्केल को मौजूदा रिएक्टरों की जीवनावधि बढ़ाने के फैसले पर तीन-महीने की रोक लगानी पड़ी और जर्मनी के 17 रिएक्टरों में से 7 को बंद करना पड़ा। यहां तक कि फुकुशिमा के बाद उनकी न्युक्लियर पालिसी के खिलाफ हुए जन विद्रोह के चलते बादेन-वुर्टेम्बर्ग में हुए चुनावों में उनकी पार्टी की करारी हार हो गई। लेकिन भारतीय न्युक्लियर संस्थानों ने हमेशा ही भारत के रिएक्टरों में सुरक्षा-सम्बंधी किसी संकट की संभावना से इंकार किया है। जापानी रिएक्टरों में हादसे के बारे में पहले पहल जब खबरें आई तो भारत में न्युक्लियर कर्ताधर्ता यहां ऐसे हादसे होने की संभावनाओं को नकारने लग गए। न्युक्लियर प्लांटों की सुरक्षा के बारे में जब मीडिया द्वारा विश्वव्यापी चिंता जताई गई, तो उसके बाद ही भारत के न्युक्लियर मुखिया ने माना कि रिएक्टरों के सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन और समीक्षा की जरूरत है। इस संबंध में विशेष चिन्ता की बात है सरकार का अपरीक्षित रिएक्टर मॉडलों को आयात करने का फैसला जिन्हें अभी तक किसी भी देश में ऑपरेट नहीं किया गया है। इनमें महाराष्ट्र में जैतपुर के लिए फ्रेंच कम्पनी आरेवा के यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर और गुजरात में छायामिति विरदी तथा आन्ध्र प्रदेश में कोव्वाडा के लिए जनरल इलैक्ट्रिक-हिताची के किफायती सरलीकृत बायलिंग वाटर रिएक्टर शामिल हैं। भारत चार विभिन्न तरह की नई लाइट वाटर रिएक्टर टैक्नोलॉजी आयात करने की योजना भी बना रहा है। इस प्रकार भारतीय रिएक्टर कॉम्पलैक्स विश्व में सबसे ज्यादा विविधता लिए हुए होगा। क्योंकि भिन्न-भिन्न तरह के रिएक्टरों के सुरक्षा मुद्दे भी भिन्न होंगे, रिएक्टरों की यह विविधता भारत की सुरक्षा संभावनाओं को अति दु:साध्य और जटिल बना देगी। यह जानी हुई बात है कि किसी भी मॉडल के लिए सुरक्षा इंजीनियरों को तैयार और ट्रेंड करने में लम्बा समय लगता है। इतने विभिन्न तरह के रिएक्टरों का होना हादसों को ही बुलावा देना है।

परमाणु बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के पीछे बुर्जुआ वर्ग का उद्देश्य

हमने पहले भी अपने लेखों के माध्यम से स्पष्ट किया है यदि कोई नई टैक्नोलॉजी लोगों का हित साधती है हमारी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार करें, तो सरकारें जितनी दूर तक चाहें न्युक्लियर पावर का विकल्प चुन सकती हैं बशर्ते कि पर्याप्त और फूल प्रूफ सुरक्षा के प्रबंध किए जा सकें और तमाम हादसे सम्बंधी समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध हों। लेकिन विज्ञान अब तक खतरनाक रेडियोधर्मी कचरे के लम्बे समय तक भण्डारण या उन्हें स्थाई तौर पर निपटाने का तरीका इजाद करने में सक्षम नहीं हुआ है। जैसा कि हमने फुकुशिमा में देखा कि इस्तेमाल हो चुकी ईंधन छड़ें रेडियोधर्मी विकिरण की उतनी ही समस्या पैदा कर रही हैं जितनी कि रिएक्टर कोर की छड़ें। भारत में फिलहाल साइट पर ही कचरे का भंडारण हो रहा है और ये पर्यावरण और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। फुकुशिमा जैसा हादसा एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें लोग भयंकर विकिरण के शिकार हो जाएंगे। तथ्य यह है कि मरणासन्न पूँजीवाद का लोगों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए न्युक्लियर सुरक्षा का पूँजीपतियों और उनकी ताबेदार सरकारों के लिए कोई मोल नहीं है। केवल एक ही उद्देश्य है जिससे वे संचालित होते हैं, वह है मुनाफा कमाना और वह भी अधिकतम। अधिकारी बेखौफ सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों और लोगों को भारी खतरे में डाल देते हैं। अक्सर वे आपराधिक लापरवाही को भी मात देते हैं। यदि हादसा हो जाए, तो वे इसके महत्व को कम करके दिखाते हैं या 'मानवीय भूल' कह कर टाल देते हैं और इस प्रकार सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों के कंधों पर डाल देते हैं। न्यूयार्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट (द हिन्दू, 12 अप्रैल, 2011) खुलासा करती है कि किस प्रकार नौसिखिए, दिहाड़ी पर काम करने वाले, अस्थाई ठेका मजदूर जो कम वेतन पर काम करते हैं, जिनकी रोजगार सुरक्षा कम है और बहुत कम हितलाभ प्राप्त करते हैं, वे ही फुकुशिमा प्लांट में ज्यादातर खतरनाक कामों को सम्भालते थे, जापान और अन्य देशों में यह आम चलन है। वे निरंतर विकिरण का शिकार होते रहते हैं यद्धपि वे डोसीमीटर साथ रखते हैं और जब विकिरण का प्रभाव अधिकतम सीमा पर पहुँच जाता है तो उन्हें काम से हटा लिया जाता है। इस प्रकार की लेबर प्रेक्टिस इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और न्युक्लियर रिएक्टरों की सुरक्षा की अनदेखी भी करती है। फुकुशिमा में सुनामी आने के बाद ज्यादातर कर्मचारियों को निकाल लिया गया था। तब से लेकर जो वहां से वापस आए थे उन्हें सख्ती से मीडिया खबरों से बचा कर रखा गया है लेकिन यही वे लोग है जो प्लांट के संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 7 अप्रैल को न्यूयार्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 21 कर्मचारियों में से सभी 100 मिलिसीवर्ट्स के स्तर के विकिरण से प्रभावित हैं जो कि एमरजैंसी के दौरान कर्मचारियों के लिए सामान्य सीमा होती है। संकट के बाद इस सीमा को 250 मिलिसीवर्ट्स तक बढ़ा दिया गया है ताकि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए बिना ही विनाशकारी एमरजैंसी काम जारी रखा जा सके। ऐसे ही मनहूस तरीके से पूँजीवाद काम करता है। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक पूँजीवादी ढाँचे में कर्मचारियों और आम आदमी के हितों की रक्षा की जाएगी। पूँजीपति वर्ग अपने वर्ग स्वार्थ में परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता के विस्तार की जरूरत के बारे में बड़ा मुखर है, कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में इसकी कारगरता का बखान कर रहा है लेकिन इसके खतरों और तबाहियों को कम करके दिखा रहा है। लोगों को पूँजीपति वर्ग की चाल असल में क्या है और न्युक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के पीछे इसकी असली साजिश क्या है यह समझ लेनी चाहिए। लोगों को खतरनाक टैक्नोलॉजी के सामने धकेल देने और उन्हें इसका शिकार बनाने वाले कदम का जोरदार विरोध होना चाहिए। यही वजह है कि पूरी दुनिया के सरोकार रखने वाले लोगों के साथ मिलकर हम माँग कर रहे हैं कि अभी जो हालात है उनमें सरकारों को बिजली उत्पादन के पर्यावरण के लिए शुभ वैकल्पिक उपायों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, छोटी-छोटी पन बिजली परियोजनाएं(मिनि हाइड्रो पावर), साफ कोयले वाली तकनीक(क्लीन कोल टैक्नोलॉजी) को जोरशोर से विकसित करने की नीति अपनानी चाहिए।

लेकिन भारत में लोगों के सतत विरोध के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार अड़ियल तरीके से अमेरिका, फ्रांस और रूस से भारी संख्या में न्युक्लियर रिएक्टरों का आयात करके उन्हें स्थापित करने के फैसले पर आमादा है। चार चुनिंदा विदेशी विक्रताओं में से प्रत्येक के पास रिएक्टरों के निर्माण के लिए समुंद्र किनारे न्युक्लियर पार्क बनाने की अलग से जगह है। इसी वजह से ही भारत-अमेरिकी सिविल न्युक्लियर करार संसद में पास किया गया और आईएईए तथा परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह के देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। निस्संदेह देशी-विदेशी एकाधिकारी पूँजी के स्वार्थ को आगे बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। विदेशी इजारेदार पूँजीपति इस सुयोग से अभिभूत हैं कि भारत के साथ भारी और लाभजनक न्युक्लियर व्यापार का मौका रहेगा जोकि उनकी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करेगा। क्योंकि विकसित देशों में न्युक्लियर पावर प्लांटों का निर्माण घट रही है इसलिए यह उद्योग न्युक्लियर टैक्नोलॉजी बेचने के लिए भारत जैसे बाजारों की तरफ अपना रुख कर रहा है। दूसरी तरफ, भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति इस लूट में बड़ा हिस्सा पाने की इंतजार में हैं और इसे पूंजीनिवेश होने और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय न्युक्लियर बाजार में अपनी पहुँच बनाने के सुअवसर के रूप में देख रहे हैं। सरकार की नीति न्युक्लियर सशस्त्रीकरण के लिए इसकी इच्छा से और क्षेत्रीय महा शक्ति (सुपर पावर) के रूप में उभरने तथा दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की इसकी महत्वाकांक्षा से भी जुड़ी हुई है। यह देखा जा रही है कि जब समाज के प्रबुद्ध तबके द्वारा जापान में हुई तबाही के बाद परमाणु बिजली उत्पादन के पूरे प्रकरण की ही सम्पूर्ण समीक्षा की जोरदार माँग उठाई जा रही है, तब भारतीय एकाधिकारी पूँजीपति सरकार को सलाह दे रहे हैं कि वह इन सबसे हतोत्साहित न हो।

ताबेदार मीडिया भी इन प्रयासों में बराबर भागीदार है। असल मुद्दों की वास्तविकता को यत्नपूर्वक छिपाया जा रही है और ज्यादातर अखबार चालाकी से सरकार की न्युक्लियर पालिसी के पीछे जन समर्थन होने की बात को उछाल रहे हैं और सत्ताधारियों के इस आश्वासन को भारी प्रचार दे रहे हैं कि भारतीय रिएक्टरों का डिज़ाइन बहुत उत्तम किस्म का है और ऐसे हादसे यहां कभी घटित नहीं होंगे।

फुकुशिमा की तबाही ने न्युक्लियर पावर प्लांटों की जोखिमभरी स्थिति को साफ तौर से उजागर कर दिया है। किसी भी न्युक्लियर हादसे का दंश आम लोगों और प्लांट कर्मचारियों और बचावकर्मियों को झेलना पड़ता है। लेकिन पूँजीपति वर्ग का इन सबसे कोई सरोकार नहीं है। जब हादसा हो जाता है तो वे इसी बात की रट लगाने में लगे रहते हैं कि ऐसे किसी हादसे की कहीं अन्यत्र होने की संभावना कितनी कम है और यह दिखाने के लिए आंकड़े उगलते रहते हैं कि कितनी कम संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और इस बात को ढकते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी संख्या कितने लम्बे समय तक प्रभावित होगी। लेकिन लोग अब इन प्रचारों से गुमराह होकर बेवकूफ बनने से इनकार कर रहे हैं। पहले से ही परमाणु बिजली के खिलाफ जन विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश सहित, एक देश के बाद दूसरे देश में लोग 'न्युक्लियर पावर कतई नहीं' का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी सरकारों से न्युक्लियर विकल्प को छोड़ने की माँग कर रहे हैं। समय की माँग है कि विभिन्न देशों में ये आन्दोलन संयोजित किये जाएं और पूँजीपति वर्ग की न्युक्लियर नीति का प्रतिरोध करने के लिए सशक्त संयुक्त जुझारू आन्दोलन गठित किया जाए। कहने की जरूरत नहीं कि न्युक्लियर विकल्प मानवजाति के लिए कितना विनाशकारी है। हम वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, शिक्षकों और समाज के सभी तबकों के सही सोच रखने वाले लोगों से अपील करते हैं कि वे नाभिकीय विनाशलीला की पुनरावृत्ति रोकने का काम पूरा करने के लिए आगे आएं।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 of Every Month

24 अप्रैल-पार्टी स्थापना दिवस...

(पृष्ठ 6 का शेष)

पूंजीवाद हमारे जीवन को चारों ओर से तबाह कर रहा है। विकराल रूप लेती जा रही महंगाई तथा बेरोजगारी से जनता परेशान है। वहीं इस साल के बजट में लाभकर रोजगार सृजित करने का कोई सुझाव नहीं है और न ही जनजीवन के बहुत जरूरी मुद्दों को हल करने का कोई उपाय है। बड़े-बड़े व्यापारियों व पूंजीपतियों को जमाखोरी व मुनाफाखोरी की खुली छूट दी जा रही है। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को कमजोर करते हुए महंगाई से राहत पाने की लोगों की बची-खुची सुविधाएं भी खत्म की जा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे क्षेत्रों का निजीकरण करते हुए जनता पर लूट-खसोट मचाने के लिये इन्हें पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 29 शहरों में पानी के पूर्ण निजीकरण की घोषणा इस दिशा में जनविरोधी कदम है। पूंजीवाद की सेवा में आम जनता पर इस तरह के हमले केन्द्र व राज्यों में सत्तासीन कांग्रेस, भाजपा सहित सभी बुर्जुआ पार्टियों के साथ-साथ नकली वामपंथी पार्टियाँ सी. पी.आई.(एम) व सी.पी.आई. भी कर रही हैं। आज कोई भी पार्टी जो पूंजीवाद की सेवा में खुद को लिप्त करेगी उसकी यह परिणति होनी लाजिमी है। मेहनतकश आम जनता में यह चाहत क्रमशः बलवती होती जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का खात्मा हो, देश के नौजवानों के लिये सुनिश्चित भविष्य हो। इन मांगों को लेकर पूंजीवाद के खिलाफ संभावित संगठित आंदोलन उठ खड़े होने के डर से देश का शासक पूंजीपति वर्ग भयभीत भी है। इसलिए वह लोगों को नैतिक रूप से कुंद बनाने, उन्हें नशे व अपसंस्कृति का शिकार बनाने, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर लोगों में फूट डालने और गलत दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार, केवल हमारे देश में नहीं, बल्कि मिस्र, ट्यूनिशिया, यमन, लीबिया, आदि देशों में भी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शोषण-अत्याचार का नजारा और जन आंदोलन के रूप में उसकी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दर्शाते हुए उन्होंने लोगों से देश के कोने-कोने में एस.यू.सी.आई.(सी) को सशक्त बनाने का आह्वान किया। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तनधारा और क्रांतिकारी नैतिकता व सर्वहारा उच्च संस्कृति के आधार पर जुझारू जन आंदोलन चलाते हुए जनता की वैकल्पिक राजनैतिक ताकत, जन संघर्ष समितियों का निमार्ण करने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने साथ-साथ विदेशों के जुझारू आंदोलन के लिए वहाँ की बहादुर जनता को सलाम देते हुए उन वीर योद्धाओं से प्रेरणा लेने और इस युग के अन्यतम महान् मार्क्सवादी चिंतनकार कॉ. शिवदास घोष के विचारों को भारत के शोषित उत्पीड़ित लोगों के बीच ले जाने की अपील की।

गुना (म.प्र.)

सभा में अन्य वक्ता म.प्र. राज्य सांगठनिक समिति के सचिव कॉ. उमा प्रसाद ने भी अपनी बात रखी। सभा की अध्यक्षता म.प्र. राज्य सांगठनिक समिति सदस्य कॉ. रामअवतार शर्मा ने की। सभा का संचालन म.प्र. राज्य सांगठनिक समिति सदस्य कॉ. जे.सी. बरई ने किया।

गुना (म.प्र.): 28 अप्रैल को स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला के सभा भवन में एसयूसीआई(सी) ने अपनी स्थापना के 63वें वर्ष पर जनसभा का आयोजन किया जिसमें पार्टी के गुना, अशोक नगर, आरोन, ग्वालियर के नेता-कार्यकर्ता-समर्थकों सहित शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुये। जनसभा में मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी), दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने कहा कि जनजीवन के हर क्षेत्र की तमाम समस्याओं का हल एकमात्र पूँजीवादी-विरोधी समाजवादी क्रांति करके ही संभव है। उन्होंने जनता से जन आन्दोलनों मे शामिल होने और एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई(सी) को मजबूत करने की अपील की।

जनसभा को पार्टी के गुना जिला प्रभारी कॉमरेड प्रदीप आर.बी., रचना अग्रवाल, रूपेश जैन ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड लोकेश शर्मा ने की।

जबलपुर: एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को जबलपुर जिला पार्टी कार्यालय में शाम को एक सभा आयोजित की गई। सभा के मुख्य वक्ता कॉमरेड उमा प्रसाद ने पार्टी गठन के इतिहास पर रोशनी डालते हुए पार्टी को मजबूत करने का सबसे आह्वान किया।

पटना (बिहार): एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की स्थापना की 63 वीं वर्षगांठ के मौके पर 24 अप्रैल, 2011 को पटना के आईएमए हॉल में पार्टी सदस्यों, समर्थकों व हमदर्दों की एक महती सभा आयोजित हुई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड शिव शंकर ने की। सभा के मुख्य वक्ता थे पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर। सभा में बिजली को फ्रेंचाइजी को देने की राज्य सरकार की योजना तथा राज्य परिवहन और निगमों को उद्योपतियों को बेचने की तीखी भर्त्सना और इसे पूरी तरह से जनहित के खिलाफ कदम बताते हुए पार्टी राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य अरुण कुमार सिंह ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

नागपुर (महाराष्ट्र): 24 अप्रैल को एसयूसीआई(सी) के 63वें स्थापना दिवस पर यहाँ विदर्भ साहित्य सम्मेलन हाल में जन सभा हुई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के उड़ीसा राज्य सचिव कॉमरेड धुर्जटी दास थे। उन्होंने कहा कि देश में सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होने से आजादी के बाद सत्ता देश के मुठ्ठीभर पूंजीपतियों के हाथों में गई। पिछले 64 साल से जारी इस पूंजीवाद शोषण-जुल्म से जनता के जीवन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारा समाज मेहनतकश वर्ग और पूंजीपति वर्ग, इन दो वर्गो में विभाजित है। पूंजीवादी शोषण-जुल्म से निजात दिलाने के लिए पूंजीवाद को क्रांति के जरिए उखाड़ फेंक कर समाजवाद करने की जरूरत है। इसीलिए कॉमरेड शिवदास घोष ने भारत की धरती पर सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की 24 अप्रैल 1948 को स्थापना की थी। इसके नेतृत्व में देश भर में आन्दोलन हो रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व में हुए सिंगूर-नदीग्राम के आन्दोलन को सफलता मिली। कॉमरेड धुर्जटी दास ने मार्क्सवाद अपनाने पर बल दिया जो एक विज्ञानों का विज्ञान है। सभा के अतिथि श्री पापडकर गुरुजी गढ़चिरोली ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉमरेड माधव भोंडे ने की। सभा का संचालन कॉ. विद्या गुरुनले ने किया। सभा में शहरी-ग्रामीण मेहनतकशों के अलावा, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों भी शामिल हुए।

पटना में 24 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com